बीएस बातचीत

हम किसानों के लिए हमेशा खड़े हैं : शिवराज सिंह चौहान

मध्य प्रदेश में शीघ्र ही विधानसभा चुनाव होने हैं। बतौर मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में अपना तीसरा कार्यकाल पूरा करने जा रहे **शिवराज सिंह चौहान** ने **संदीप कुमार** से अपनी सरकार की उपलब्धियों, किसान आंदोलन और अन्य मुद्दों पर बातचीत की। प्रस्तुत हैं साक्षात्कार के अंश:

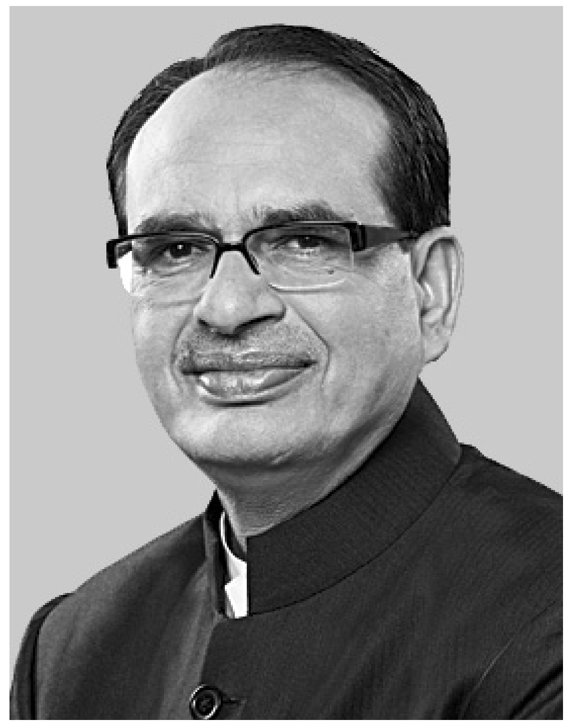

मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव करीब हैं। क्या आपको लगता है कि राज्य में सत्ता विरोधी लहर है?

मुझे नहीं लगता कि प्रदेश में कोई सत्ता विरोधी लहर है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार लगातार लोगों से किए तमाम वादे पूरे करने की दिशा में काम करती रही है। इसका नतीजा भी हर कोई देख सकता है। सन 2003 में हमें कांग्रेस से एक बीमारू राज्य विरासत में मिला था। हमने उसे एक विकसित राज्य में परिवर्तित किया है। जनता इसकी गवाह है। जन आशीर्वाद यात्रा को मिल रहा लोगों का स्नेह इसका प्रमाण है। मैं जहां भी जाता हूं, हर वर्ग के लोग बड़ी संख्या में आते हैं और मुझे अपना आशिष देते हैं।

जहां तक कांग्रेस की बात है, उसमें न तो मुझे कोई नया उत्साह नजर आ रहा है और न ही लोगों को। वह अभी भी कई धड़ों में बंटी हुई है। वहां हर कोई अपना एजेंडा आगे बढ़ाने की जुगत में लगा हुआ है। आए दिन यह सुनने को मिलता है कि उनके राज्य प्रभारी को किसी न किसी नेता के समर्थकों ने पीट दिया। मैंने अपने गृहमंत्री से कहा कि वे उनसे बात करें और उन्हें सुरक्षा मुहैया कराएं। मुझे दुख होता है यह देखकर। कांग्रेस में आपसी मतभेद बहुत हैं।

बीते कुछ वर्षों में घोटाले, अवैध खनन, किसानों की आत्महत्या और उनके विरोध प्रदर्शन सामने आए हैं। इससे आपकी छवि को धक्का पहुंचा है। क्या इसका असर पार्टी के आत्मविश्वास पर भी होगा?

भाजपा काडर आधारित पार्टी है। ऐसा असर न कभी हुआ है और न होगा। हम कांग्रेस-मुक्त भारत बनाने को लेकर एकजुट हैं। हम काफी हद तक इस लक्ष्य के करीब हैं क्योंकि कांग्रेस चार राज्यों तक सिमट कर रह गई है। जब हम घोटालों की बात करते हैं तो व्यापमं घोटाले का जिक्र अनिवार्य है। यह दिग्विजय सिंह के समय से चला आ रहा था और मैं इसे सामने लाया। हमें इसका श्रेय मिलना चाहिए। हमने तमाम प्रमुख नदियों में हर तरह के खनन पर रोक लगाई और जहां कानूनी मंजूरी वाली खदानें चल भी रही हैं, वहां पंचायतों को खनन और इसके प्रबंधन का दायित्व सौंपा गया है।

प्रदेश में किसानों के सामने इकलौती समस्या फसल के बंपर उत्पादन की है। हम किसानों के लिए हमेशा खड़े हैं। असली किसान कभी विरोध प्रदर्शन करने नहीं जाते। अधिकांश प्रदर्शन विपक्ष द्वारा प्रदेश की शांति भंग करने के लिए आयोजित किए जाते हैं।

एक ओर राज्य में आनंद विभाग का गठन किया गया है, दूसरी ओर हाल के दिनों में अचानक बलात्कार की घटनाओं में वृद्धि हुई है। यह कानून व्यवस्था की समस्या है? इसे कैसे देखते हैं?

मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने आनंद विभाग का गठन किया। हमारा जोर लोगों के जीवन में खुशियां लाने पर है। बलात्कार की घटनाएं हमेशा परेशान करती हैं, फिर चाहे ऐसा मध्य प्रदेश में हो या देश के किसी अन्य हिस्से में। मेरा दृढ़ विश्वास है कि ऐसे घृणित अपराध करने वालों को सभ्य समाज में रहने का अधिकार नहीं है। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने गत वर्ष दिसंबर में 12 वर्ष तक की अल्पवय बच्चियों के बलात्कारियों के लिए फांसी की सजा का प्रावधान किया। इस समस्या से निपटने के लिए समाज को अपने भीतर झांकना होगा और व्यवहार में बदलाव लाना होगा। हमें अपने बच्चों को सही गलत में भेद करना सिखाना होगा।

केंद्र सरकार की मेक इन इंडिया योजना के तत्काल बाद आपने मेक इन मध्य प्रदेश योजना की घोषणा की थी। इस दिशा में क्या प्रगति हुई?

मेक इन मध्य प्रदेश के अधीन कई पहल की गई हैं। देश की पहली छोटे हथियार बनाने वाली फैक्टरी मालनपुर में लगाई गई है। यह इजरायल वीपन इंडस्ट्रीज और पुंज लॉयड का संयुक्त उपक्रम है और देश में अपनी तरह का पहला उद्यम भी है। हमने रक्षा खरीद निवेश प्रोत्साहन नीति तैयार की है। निवेश अभिरुचि को वास्तविक निवेश में बदलने की हमारी दर कई राज्यों से बेहतर है।

> अच्छी सड़क, हवाई संचार, अधिशेष बिजली व पानी की आपूर्ति से बेहतर बुनियादी ढांचा तैयार किया गया है। निवेशकों को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं।

राज्य सरकार ने विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में प्रगति के लिए कौन से खास तरीके अपनाए हैं?

राज्य में निवेश को सुविधा प्रदान करने और उसे बढ़ाने के लिए एकल खिड़की व्यवस्था लागू की गई है। कारोबारी सुगमता में हमें पूरे देश में सातवां स्थान दिया गया है। अच्छी सड़क, हवाई संचार, अधिशेष बिजली और पानी की आपूर्ति की मदद से बेहतर बुनियादी ढांचा तैयार किया गया है। संभावित निवेशकों को भी हम तमाम प्रोत्साहन दे रहे हैं। चंबल एक्सप्रेसवे के रूप में औद्योगिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है जो व्यापारिक गतिविधियों के अंतरराज्यीय आवागमन को गति देगा। हम मध्य प्रदेश को एक लॉजिस्टिक केंद्र के रूप में विकसित करना चाहते हैं।

कुछ समय पहले आपने कहा था कि मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिका की सड़कों से बेहतर हैं। लेकिन जब हम बड़े शहरों से ग्रामीण इलाकों में जाते हैं तो यह सच नहीं लगता।

यह सवाल मुझसे कई बार पूछा जा चुका है और मेरा जवाब वही रहा है। मैं अमेरिका गया था निवेश और उद्योग के केंद्र के रूप में मध्य प्रदेश का प्रचार करने। मैं एक तरह से प्रदेश का सीईओ हूं जो यहां के 7.5 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। मैंने वह बयान बतौर सीईओ दिया था और मैं उस पर कायम हूं। इंदौर एयरपोर्ट की ओर जाने वाली सड़क वॉशिंगटन डीसी की सड़क से काफी बेहतर है।

प्रदेश में काफी उत्साह के साथ वैश्विक निवेश सम्मेलन आयोजित किए गए। परंतु उनका कोई लाभ नहीं नजर आ रहा।

वैश्विक निवेश एक लंबी प्रक्रिया है। एक दिन में कुछ नहीं हो सकता। इसके लिए निवेशकों के साथ निरंतर संपर्क में रहने की जरूरत पड़ती है। हमें इसमें काफी सफलता मिली है। इन्फोसिस और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जैसी आईटी क्षेत्र की बड़ी कंपनियां मध्य प्रदेश में आ रही हैं। वर्ष 2017 में देश के कुल निवेश में 16.4 फीसदी हिस्सेदारी के साथ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर रहा। हम छोटे हथियार बनाने वाली फैक्टरी के बारे में पहले बात कर ही चुके हैं।

पूंजीगत निवेश और रोजगार को लेकर भी वास्तविक आंकड़े नजर नहीं आते।

राज्य में औद्योगिक पार्क और विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाए गए हैं और उनको अच्छी प्रतिक्रिया भी मिली है। बिना वास्तविक निवेश के यह संभव नहीं था। मालनपुर हथियार फैक्टरी, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट आदि ने राज्य में रोजगार तैयार किए हैं। हमें 2017 में कुल निवेश का 16 फीसदी हासिल हुआ। यह तो हो गई आंकड़ों की बात। आज देश भर में स्वरोजगार पर जोर दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी 26.83 लाख से अधिक लोगों को मुद्रा ऋण दिया जा चुका है।

> "किसान आत्महत्या एक गंभीर मुद्दा है। इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए और न ही इसे अलग-थलग करके देखा जाना चाहिए। जब मैंने मुख्यमंत्री पद संभाला, तब कृषि विकास दर गिर रही थी। मुझे लगा कि यह तो अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। आबादी का दो तिहाई हिस्सा खेती पर निर्भर है। हम बिना कृषि सुधार के कैसे आगे बढ़ेंगे? हमने सिंचित भूमि का रकबा 7.5 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 40 लाख हेक्टेयर किया है और आगे इसे 80 लाख हेक्टेयर तक ले जाने की योजना है। प्रदेश में कृषि क्षेत्र में जो बदलाव आया है उस पर तो अध्ययन होना चाहिए"
>
> **शिवराज सिंह चौहान**
> मुख्यमंत्री

कुछ वर्ष पहले आपने विजन 2018 की बात की थी। 2018 का लगभग दो तिहाई वक्त बीत चुका है और चुनाव करीब हैं। उस विजन का क्या हुआ?

हमारे विजन 2018 में तीन रुख शामिल थे। पहला, मध्य प्रदेश को बीमारू समूह से बाहर लाना, दूसरा, जरूरी बुनियादी ढांचे के साथ उसे विकासशील राज्य बनाना और तीसरे चरण में निवेश जुटाकर और कृषि को बढ़ावा देकर उसे एक विकसित राज्य बनाना। मुझे खुशी है कि हम विजन 2018 के लक्ष्यों को हासिल करने में सफल रहे हैं।

हमने गरीबों और वंचितों के लिए जनकल्याण (संबल) योजना शुरू की। इस योजना के तहत उनके लिए पक्का आवास बनाया जा रहा है। बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा और 5 लाख रुपये तक की चिकित्सा सहायता दी जा रही है। हमें उम्मीद है कि हम संबल के जरिये लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकेंगे।

कृषि क्षेत्र में एक खास तरह का विरोधाभास देखने को मिल रहा है। एक ओर प्रदेश में 18 फीसदी से अधिक की कृषि विकास दर है और लगातार कृषि कर्मण अवार्ड मिल रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर किसान परेशान हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक बीते 10 सालों में 11,000 से अधिक किसान आत्महत्या कर चुके हैं।

किसान आत्महत्या एक गंभीर मुद्दा है। इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए और न ही इसे अलग-थलग करके देखा जाना चाहिए। जब मैंने मुख्यमंत्री पद संभाला, तब कृषि विकास दर घट रही थी। मुझे लगा कि यह तो अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। आबादी का दो तिहाई हिस्सा खेती पर निर्भर है। हम बिना कृषि सुधार के कैसे आगे बढ़ेंगे? हमने सिंचित भूमि का रकबा 7.5 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 40 लाख हेक्टेयर किया है और आगे इसे 80 लाख हेक्टेयर तक ले जाने की योजना है। प्रदेश में कृषि क्षेत्र में जो बदलाव आया है उस पर तो अध्ययन होना चाहिए।

बीते कुछ वर्षों में सरकार ने कई योजनाओं की घोषणा की है। संबल योजना, सरल बिजली बिल माफी योजना, कृषक समृद्धि योजना, भावांतर भुगतान योजना। क्या राज्य की वित्तीय स्थिति इतनी अच्छी है कि वह इतना वित्तीय बोझ सहन कर पाए?

हां, हम इन तमाम योजनाओं का वित्तीय बोझ उठाने में सक्षम हैं। हमने प्रदेश में विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा विकसित करने में काफी धन खर्च किया है। अब हम उस चरण से आगे बढ़ चुके हैं और अब इन संपत्तियों के रखरखाव की आवश्यकता है। हम आगे समाज कल्याण योजनाओं के लिए संसाधन जुटा रहे हैं। वर्ष 2018-19 के हमारे बजट में राजकोषीय घाटा मध्य प्रदेश राजकोषीय जवाबदेही एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत 3.23 फीसदी की तय सीमा के भीतर है।

आपके बड़े पुत्र कार्तिकेय सिंह को हाल के दिनों में पार्टी का प्रचार करते देखा गया है। क्या वह आगामी चुनाव में सक्रिय राजनीति में उतरेंगे?

कार्तिकेय नौजवान हैं और वह अपनी पसंद का करियर चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के विकास कार्य में वह उसी तरह मेरी मदद करते हैं जिस तरह कोई भी पुत्र अपने पिता की करेगा। जहां तक सक्रिय राजनीति में आने की बात है यह पूरी तरह उन पर निर्भर करता है। हां, अगर वह जन सेवा करना चाहते हैं तो उनको सीढ़ियां चढ़कर नीचे से ऊपर आना होगा। हमारी पार्टी वंशवाद में यकीन नहीं करती। उन्हें खुद को साबित करना होगा।

'जानिये क्यों गिर रहा है रुपया'

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने रुपये की गिरावट को थामने की हरसंभव कोशिश करने का भरोसा दिलाया है। इसका असर पिछले सत्र में तत्काल देखने को मिला कि डॉलर के मुकाबले रुपये में जबरदस्त रिकवरी देखने को मिली। हालांकि रुपये में और रिकवरी की अभी दरकार है।

डॉलर के मुकाबले रुपया बुधवार को रिकॉर्ड 72.91 के स्तर तक लुढ़कने के बाद संभला और 72.19 रुपये प्रति डॉलर के मूल्य पर बंद हुआ। इससे पहले मंगलवार को 72.69 पर बंद हुआ था। रुपये की गिरावट से अभिप्राय डॉलर के मुकाबले रुपये में कमजोरी आना है। सरल भाषा में कहें तो इस साल जनवरी में जहां एक डॉलर के लिए 63.64 रुपये देने होते थे वहां अब 72 रुपये देने होते हैं। इस तरह रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ है।

शेष दुनिया के देशों से लेन-देन के लिए प्राय: डॉलर की जरूरत होती है ऐसे में डॉलर की मांग बढ़ने और आपूर्ति कम होने पर देशी मुद्रा कमजोर होती है। एंजेल ब्रोकिंग के करेंसी एनालिस्ट अनुज गुप्ता ने रुपये में आई हालिया गिरावट पर कहा,

''भारत को कच्चे तेल का आयात करने के लिए काफी डॉलर की जरूरत होती है और हाल में तेल की कीमतों में जोरदार तेजी आई है जिससे डॉलर की मांग बढ़ गई है। वहीं, विदेशी निवेशकों द्वारा निवेश में कटौती करने से देश से डॉलर का आउट फ्लो यानी बहिर्गामी प्रवाह बढ़ गया है। इससे डॉलर की आपूर्ति घट गई है।''

उन्होंने बताया कि आयात ज्यादा होने और निर्यात कम होने से चालू खाते का घाटा बढ़ गया है, जोकि रुपये की कमजोरी की बड़ी वजह है। ताजा आंकड़ों के अनुसार, चालू खाते का घाटा तकरीबन 18 अरब डॉलर हो गया है। जुलाई में भारत का आयात बिल 43.79 अरब डॉलर और निर्यात 25.77 अरब डॉलर रहा। वहीं, विदेशी मुद्रा का भंडार लगातार घटता जा रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार 31 अगस्त को समाप्त हुए सप्ताह को 1.19 अरब डॉलर घटकर 400.10 अरब डॉलर रह गया। गुप्ता बताते हैं, ''राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बनने से भी रुपये में कमजोरी आई है। आर्थिक विकास के आंकड़े कमजोर रहने की आशंकाओं का भी असर है कि देशी मुद्रा डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रही है। जबकि विश्व व्यापार जंग के तनाव में दुनिया की कई उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं की मुद्राएं डॉलर के मुकाबले कमजोर हुई हैं।''

अमेरिकी अर्थव्यवस्था में लगातार मजबूती के संकेत मिल रहे हैं जिससे डॉलर दुनिया की प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले मजबूत हुआ है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मजबूती आने से विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से अपना पैसा निकाल कर ले जा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि संरक्षणवादी नीतियों और व्यापारिक हितों के टकराव के कारण अमेरिका और चीन के बीच पैदा हुई व्यापारिक जंग से वैश्विक व्यापार पर असर पड़ा है। **-आईएएनएस**

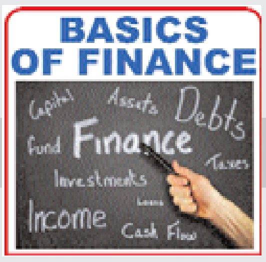

34

PSU बैंकों का भविष्य

पंजाब नेशनल बैंक के 12,000 करोड़ रूपये घोटाले के उजागर के बाद से आम आदमी आशंकित है। सरकारी बैंकों की Financial Position भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है।

NPA बढ़ता जा रहा है। कई छोटे बैंकों में तो NPA का स्तर 15% - 20% तक हो। गया है। सरकार को Loans के लिये दीर्घकालीन स्पष्ट नीति बनानी चाहिये। सरकारी हस्तक्षेप बिल्कुल खत्म होना चाहिये।

आज सारे सरकारी बैंकों (एक-दो को छोड़कर) को Capital की बहुत ज्यादा जरूरत है। सरकार को बैंकों में एक मुश्त राशि Capital Infuse करने से ही सरकारी बैंको की दशा सुधर सकती है। लेकिन यह समस्या का स्थायी समाधान नहीं है।

समस्या का स्थायी समाधान PSU बैंकों को मिलाकर 4-5 बड़े PSU बैंक बनाना व Loan में सरकारी हस्तक्षेप को कम से कम करना है। छोटे-छोटे बैंक को मिलाकर बड़ा बैंक बनाने से खर्चे में कमी के साथ-साथ गुणवत्ता में सुधार होगा। कम्पटीशन भी आपस में कम होगा।

आज प्राइवेट बैंक डबल डिजीट (Double Digit) में कम से कम Growth कर रहे हैं। NPA का स्तर बहुत सीमा तक Control में है। वहीं PSU बैंक NPA की बढ़ती प्रोविज़निंग के कारण Loss में आते जा रहे हैं। अब समय आ गया है कि सरकार जरूरतमंद को Loan आसानी से दे लेकिन घोटाला नहीं हो, ऐसी दीर्घकालीन नीति बनाये तभी देश में PSU बैंकों का भविष्य उज्जवल होगा। PSU बैंकों को मर्जर से बैंकों को सुदूर दूर क्षेत्र में भी E&pansion करने में आसानी व सुविधा रहेगी। देखते हैं कि आगे क्या होता है।

सरकार की मंशा नीयत व बैंकों के विकल्प पर ही PSU बैंकों का भविष्य निर्भर है।

- राजेश कुमार सोढानी
(लेखक जयपुर आधारित फाइनेंशियल एडवाइजर हैं)

Continuous Upper Circuit Last Week

Scrip Name	10 Sep.	11 Sep.	12 Sep.	13 Sep.	14 Sep.	% Chg
PRAXIS	217.9	228.75	240.15	-	252.15	27.28
SADHNANIQ	1069.8	1123.25	1179.4	-	1238.35	21.54
JAINSTUDIO	4.2	4.41	4.63	-	4.86	21.5
DELTAMAGNT	96.6	101.4	106.45	-	111.75	21.47
KRETTOSYS	11.46	12.03	12.63	-	13.26	21.43
BHASKAGR	17.54	18.41	19.33	-	20.29	21.42
CAMSONSEEDS	10.3	10.81	11.35	-	11.91	21.41

Continuous Lower Circuit Last Week

TINNATFL	32.05	30.45	28.95	-	27.55	-22.61
PREMSYN	203.25	193.1	183.45	-	174.3	-18.51
MKEXIM	7.81	7.42	7.05	-	6.7	-18.49
SOUTLAT	7.22	6.86	6.52	-	6.2	-18.42
TEXMOPIPES	36.95	35.15	33.4	-	31.75	-18.28
PFLINFOTC	4.9	4.66	4.43	-	4.21	-18.25
CLLIMITED	8.59	8.17	7.77	-	7.39	-18.25

Major Gainers Last Week

Scrip	Price 7.09.18	Price 14.09.18	% Chg.
INDOKEM	15.96	23.57	47.68
CAMEXLTD	33.95	49.25	45.07
SIMBHALS	9.23	12.93	40.09
DHAMPURSUG	85.35	117.05	37.14
COSMOFE	19	25.95	36.58
SAKHTISUG	12.75	17.32	35.84
PIXTRANS	200.1	270.3	35.08
AVADHSUGAR	353.6	472.65	33.67
JCTLTD	1.92	2.56	33.33
FLEXITUFF	35.3	46.2	30.88
RENUKA	11.46	14.87	29.76
MAWANASUG	45.8	59.4	29.69
MAGADHSUGAR	82.45	106.8	29.53
DWARKESH	19.05	24.65	29.4
DALMIASUG	60.6	78.05	28.8
EMMESSA	29.65	38.15	28.67
KIOCL	177.65	227.85	28.26
UGARSUGAR	12.69	16.26	28.13
TRIVENI	38	48.65	28.03
UTTAMSUGAR	85.8	109.35	27.45
PRAXIS	198.1	252.15	27.28
TOYAMIND	5.37	6.8	26.63
BAJAJHIND	6.73	8.52	26.6
JAIBALAJI	10.18	12.79	25.64
KMSUGAR	8.66	10.8	24.71

Major Losers Last Week

Scrip	Price 7.09.18	Price 14.09.18	% Chg.
GTNINDS	22.3	14.75	-33.86
TINNATFL	35.6	27.55	-22.61
TATAYODOGA	78.85	61.55	-21.94
IL&FSENGG	16.8	13.25	-21.13
IL&FSTRANS	30.1	23.75	-21.1
VIVANTA	12.7	10.25	-19.29
PREMSYN	213.9	174.3	-18.51
MKEXIM	8.22	6.7	-18.49
PROVESTSER	9.33	7.62	-18.33
TEXMOPIPES	38.85	31.75	-18.28
CLLIMITED	9.04	7.39	-18.25
PFLINFOTC	5.15	4.21	-18.25
JATTAINDUS	22.2	18.15	-18.24
GOYALASS	3.53	2.89	-18.13
TPLPLAST	322.15	265.65	-17.54
SKYLMILAR	2.65	2.19	-17.36
UNISTRMU	5.92	4.9	-17.23
TTIENT	0.91	0.76	-16.48
ISFT	198.5	165.95	-16.4
ALFAICA	40.25	33.65	-16.4
SUNILHITEC	2.41	2.02	-16.18
DIAPOWER	2.58	2.17	-15.89
ADORMUL	47.4	39.9	-15.82
VASINFRA	5.4	4.55	-15.74
MADHUCON	10.82	9.15	-15.43